IJASRM
International Journal of Advanced Scientific Research and Management, Special Issue 5, April 2019
www.ijasrm.com
ISSN 2455-6378

मध्य प्रदेष राज्य के ग्रामीण विकास में सरकारी योजनाओं का योगदान

डॉ. मोनिका मालविया [१] मृदुलता सिकरवार [२]
[१] सह प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, रविन्द्रनाथ टैगोर विष्वविद्यालय, भेापाल;म. प्र.द्ध भारत
[२] षोधार्थी वाणिज्य विभाग, रविन्द्रनाथ टैगोर विष्वविद्यालय, भेपाल;म. प्र.द्ध भारत

षोध सारांष-*ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए कुषल तथा सक्षम सरकार की जरूरत होती है क्योंकि कुषल सरकार होगी तभी तो ग्रामीण स्तर का विकास होगा तथा उसके द्वारा ही ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संचालन होता है। गॉवों के विकास के संम्बंध में यही प्रषासन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आर्थिक विकास के लिए जहॉ पर योजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है वही पर इसके विवेक पूर्ण निर्माण और सही से क्रियान्वित करने का भी उतना ही महत्व है किसी भी सरकारी योजना के निर्माण की सफलता उसके सही से निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन पर आधारित होती है। इस प्रकार से देखा जाए तो विकास कार्यक्रमों का संचालित करना सरकार का ही दायत्व होता है। अतः ग्रामीण प्रषासन की दक्षता पर ध्यान देने की आवष्यकता है। ग्रामीण विकास को अब राष्ट्रीय उन्न्ती और सामाजिक कल्याण के लिए अनिवार्य माना जाने लगा है। समस्या केवल ग्रामीण विकास की ही नहीं है बल्की ग्रामीण समाज जिसमें हमारा मध्यप्रदेष समाहित है उसके विकास की है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को राज्य के उत्पादन एंव वर्तमान प्रतिव्यक्ति आय में न्याय पूर्ण प्रति अंष प्राप्त होना चाहिए। प्रस्तुत षोध पत्र में वर्णात्मक षोध विधि का अध्ययन किया है एंव समंको का संकलन द्वितीयक स्त्रोत से किया है। प्रस्तुत षोध पत्र का मुख्य उद्देष्य मध्यप्रदेष राज्य के ग्रामीण विकास में सरकारी योजनाओं के योगदान का अध्ययन करना है।*

१. प्रस्तावना

ग्रामीण विकास से आषय लोगों का आर्थिक सुधार और उनके सामाजिक बदलाव दोनो से लगाया जाता है अर्थात ग्रामीण जनसंख्या के सर्वागीय सन्तुलित विकास से होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या का सही से विकास न हो पाना है, परन्तु पिछले कुछ वर्षो से ग्रामीण विकास अवधारणओं में बहुत सारे परिवर्तन हुए है विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है। ग्रमीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की बढती हुई भागीदारी, योजनाओं का विकेन्द्रीकरण , भूमिसुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना और ऋण की आसानी से उपलब्धी करवाकर ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाना ही मध्य प्रदेष सरकार लक्ष्य है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से गॉवों का सन्तुलित विकास करना प्राथमिक आवष्यकता है साथ ही औधोगिक प्रक्रति के लिए भी यह अति आवष्यक है। ग्रामीण विकास का सम्बध देष की ७० प्रतिषत जनसंख्या से लगाया जाता है। मध्यप्रदेष का ग्रामीण विकास जहॉ कृषि, पषुपालन, और कुटीर उद्योगों के विकास पर निर्भर करता है वही कार्यो को करने के लिए संसाधनों का होना भी जरूरी है अतः ग्रामीण रोजगार भी उतना ही जरूरी है जिससे कि गॉवों की निर्धनता को दूर किया जा सके तथा स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद मध्यप्रदेष सरकार ने ग्रामीण स्तर पर विकास करने के अनेक प्रयास किए है।

राज्य स्तर पर समस्त विकास कार्यक्रम जैसे - आई.आर.डी.पी. , एन.आई.ई.पी. , आर.एल.ई.जी.पी. , डी.पी.ए.पी. आदि एक ही विभाग के द्वारा संचालित किए जाते है। इसके सम्बंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निर्देष भी दिए है। जब ग्रामीण विकास के लिए कोई विषेष कार्यक्रम किया जाता है तो उसके लिए एक अलग आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। इसके अन्तर्गत एक आयुक्त, उपायुक्त, तीन सहायक आयुक्त कार्यपाल यंत्री आदि अधिकारी कार्य करते है।

ग्रामीण विकास योजनाओं का मुख्य उद्देष्य ग्रामीण क्षेत्रों का बहुआयामी विकास करना है जिसके अन्तर्गत ग्रामीणों को स्व-रोजगार के सृजन, ग्रामीण निर्धन लोगों के लिए आवास तथा कृषि के लिए सिचाई के साधनों का प्रबन्ध करना, गॉवों में सही सड़को का निर्माण करना, ग्रामीण बच्चों के लिए उच्च षिक्षा की व्यवस्था करना तथा इसके साथ- साथ पंचायती राज संस्थान की एंव मानव संसाधन विकास आदि कार्य इसके अन्तर्गत आते है।

IJASRM International Journal of Advanced Scientific Research and Management, Special Issue 5, April 2019
www.ijasrm.com
ISSN 2455-6378

ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रमों में ,प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ;पीएमजीएसवाईद्ध,ग्रामीण आवास ;आरएच द्ध, महात्मागांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी अधिनियम मनरेगा , स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना ;एसजीएसवाईद्ध ग्रामीण आजिविका राष्ट्रीय मिषन ;एलआरएलएमद्ध और मध्यप्रदेष सरकार के द्वारा अनेक सुख सुविदाए दी जा रही है

१६ वीं षताब्दी के अन्तिम वर्षों में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया ,औधैगिक क्रान्ती के कारण तीव्र होती गई और सभ्यता का विकास होते होते गॉवों की झोपड़ियों तक पहुच गई और ग्रामीण स्तर पर रहने वाले लोगों का विकास करने के लिए मध्यप्रदेष सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने लगा जिसमें व्यक्तियों के लिए सही रोजगार उपलब्ध कराना, स्वास्थ एंव षिक्षा में सुधार लाना ,संचार व्यवस्था का विस्तार करना एंव आवासीय स्थिति सुधारना आदि योजनाओं का निर्माण क्योंकि ग्रमीण व्यक्तियों की गरीबी प्रायः कम उत्पादन , स्वास्था सम्बंधी सही जानकारी न होना तथा अल्परोजगार के परिणामस्वरू होती है। इसलिए राज्य सरकार के द्वारा उत्पादकता और रोजगार के अवसरों में व्रद्धिकरना भीएक महत्वपूर्ण योगदान है।यह एक एसी व्यूह रचना है जो व्यक्तियों को एक विषिष्ट समूह तथा ग्रामीणों के आर्थिक विकास एंव सामाजिक जीवना को उन्नत करने के लिए बनाई गयी है।जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। और यदि इन सभी व्यवस्थाओं के बाबजूत भी निर्धनता, असमानता, और बेरोजगारी में कमी नही आई तो सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं होगा।

ग्रामीण समुदाय का विकास करना वहॉ की राज्य सरकार का उत्तरदायत्व होता है। प्रत्येक राज्य पर एक विकास समिति होती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री तथा उसके साथ समस्त विकास विभागों के मंत्री उसके सदस्य होते है। समिति का सदस्य एक विकास आयुक्त होता है। उसी के द्वारा ग्रमीण विकास के सभी कार्यक्रमों एंव नीतियों के बीच सम्बंध स्थापित किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में समय - समय पर परियोजनाओं, कार्यक्रमों,तथा विभिन्न योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है।इन कार्यक्रमों को और प्रभावी व गतिमान बनाने के लिए इन्हें पचायती राज्य से जोड़ने की योजना है। वैसे तो ग्रामीण विकास की सरकारी परियोजनाओं और कार्यक्रमों ने गॉवों की प्रगति में आवष्यक भूमिका निभई है किन्तु अभी भी यह कहा जा सकता कि ग्रामीणों को अभी भी इन परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का सही से लाभ नहीं मिल पाता है। अभी भी कई गॉव ऐसे है जिनमें सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा वैज्ञानिक, तकनीकीआदि क्रियाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है।

२. साहित्य की समिक्षा

किसी भी षोध अध्ययन में साहित्य की समिक्षा करना अनिवार्य होता है क्योंकि यह एक आधार षिला की भाति होता है और षोधार्थी का कार्य इसी पर आधारित होता है।षोध कार्य पर उपलब्ध साहित्य का विस्तारपूर्वक अध्ययन षोध कार्य को थोड़ा सरल बना देता है। प्रस्तुत अध्ययन में साहित्य की समिक्षा इस प्रकार की है

१ –श्री पटेल, संदीप –

ष्षोध अध्ययन –''एकीक्रत ग्रामीण विकास के क्रियान्वयन की समस्या का अध्ययन किया''

निष्कर्ष –

१. अधिकांष हितग्रहियों का एक जैसा व्यवहार अपनाना।
२. ७० प्रतिषत लाभ भोगी की आय में व्रद्धि होना।
३. ६५ प्रतिषल लाभ भोगी का ऋण वापसी ।

२ – भट्ट, जी.डी. –

षोध अध्ययन –'' इवैल्यूषन ओफ द आई. आर.डी.पी. में ,प्रोग्राम एस्टडी '' में आई. आर. डी. पी. तथा हितग्रहियों के मध्य समानता के लिए सुझाव दिए

निष्कर्ष - जिले में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों और ग्रमीण लोगों के मध्य समन्वय का होना अत्यंत जरूरी है कि जब भी ग्रामीण विकास के लिए योजनाऐं बनाई जाये उसमें ग्रामीण लोगों ,कारिगरों तथा नीचले स्तर के कर्मचारियों को भी सम्मलित किया जाए ,जिससें कि योजना के क्रियान्वयन में कोई समस्या न हो और धन भी अधिक व्यर्थ न हो।

३. षोध के उद्देष्य

प्रस्तुत ष्षोण के प्रमुख उद्देष्य निम्न है

;कद्धमध्यप्रदेष राज्य के ग्रामीण विकास में सरकारी योजनाओं के योगदान का अध्ययन करना।

;खद्ध ग्रामीण विकास के महत्व को समझाना।

IJASRM International Journal of Advanced Scientific Research and Management, Special Issue 5, April 2019
www.ijasrm.com
ISSN 2455-6378

;गद्ध ग्रामीण विकास की समस्याओं के सम्बंध में सुझाव प्रस्तुत करना ।

४. षोध प्रविधि

प्रस्तुत ष्षोध प्रविधि में द्वितीय समंको का प्रयोग किया गया है। द्वितीय समंक वे समंक होते है जिनके विषय में पहले से संकलित सामग्री होती है द्वितीय समंक कहलाते है। इनके अन्तर्गत वे सामग्री आती है जो पहले से प्रकाषित या अप्रकाषित रूप में कही न कही उपलब्ध होती है। द्वितीय समकों के मुख्य स्त्रोत - पुस्तकें, पुस्तकालय, समाचार पत्र, सरकारी प्रतिवेदन तथा इंटरनेट आदि होते है।प्रस्तुत षोध में इन सभी का सहारा लिया।

५. षोध अध्ययन का क्षेत्र

किसी भी कार्य को करने से पहले कार्य का क्षेत्र निर्धारित कर लेना चाहिए। प्रस्तुत षोध में मध्य प्रदेष के ग्रामीण विकास में सरकारी योजनाओं के योगदान का अध्ययन किया है कि किस प्रकार से सरकारी योजनाऐं ग्रामीण विकास में सहायक है।

६. चुनौतियां

ग्रामीण विकास में चुनौतियां निम्नलिखित है।

;कद्ध कुछ गॉव तो ऐसे है जहॉ पर सरकारी योजनाओं का विकास ही नही हुआ है।

;खद्ध गॉवों में लोग अधिक प्रषिक्षित नहीं होते है जिसकी बजह से वे सरकारी योजनाओं को सही सें समझा भी नहीं पाते।

;गद्ध परियोजनाओं में समय - समय पर कई परिर्वतन होते रहते है जिसकी बजह से भी सही से विकास नहीं हो पाता।

;घद्ध कार्यक्रम के प्रति लोगों में जानकारी का अभाव भी एक समस्या का कारण है।

;ड़द्ध सरकारी विभागों ,अभिकरणों आदि में आपसी तालमेल का भी अभाव पाया जाता है यह भी एक समस्या का कारण है।

७. समाधान के लिए सुझाव

प्रस्तुत षोध के लिए निम्न लिखित सुझाव प्रस्तुत किए है

;कद्ध वास्तिविक मापदण्ड के आधार पर सम्भावित लाभ भोगियों की उचित पहचान करना।

;खद्ध आधारभूत वित्त संस्थाओं एंव स्त्रोतों की संख्या बढ़ाना तथा प्रषासनिक और बैंकिंगकी सही से व्यवस्था करना।

;गद्ध कार्यक्रमों के प्रति लोगों को घर-घर जाकर जानकारियां प्रदान करना।

;घद्ध गॉवों में प्रषिक्षण की सही व्यवस्था करना ।

;ड़द्ध गॉवों को जगरूक करने के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करना।

टप्पनिष्कर्ष

सम्पूर्ण षोध से यह निष्कर्ष निकताहै कि मध्य प्रदेष के ग्रामीण विकास में सरकारी योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्ही योजनाओं की बजह से गॅवों का विकास सम्भाव हो पाया है परन्तु फिर भी अभी सरकार को इसपर और ध्यान देने की जरूरत है जिससे कि सभी गॉवों का सही से विकास हो सके।

ग संदर्भ सूचि

१. डॉ. मालवीय ,हरीषचन्द्र - ''समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम '', ग्रामीण विकास समिक्षा, अंक ६ ,खंड २ जुलाई - दिस. १९९० पृष्ठ दृ ४५- ४८ , एम. आई. आर.डी. हैदराबाद

२. डॉ. भट्ट ,जी. डी. - '' इवेल्यूषन ओफ द आई. आर. डी. पी. ,प्रोग्राम ए स्टडी '' कुरूक्षेत्र , नवम्बर १९८९, पृष्ठ ३६- ४१

३. पटेल संदीप - ''एकीकृत ग्रामीण विकास के क्रियान्वयन की समस्या'' ,ग्रामीण विकास समीक्षा खण्ड-१ अंक- १० ,जुलाई ,दिसम्बर ,१९९१ पृष्ठ ४१- ४७

४. समाचार पत्र - राज एक्सप्रेस